नाई, उचित भंडारण की सुविधा का अभाव, आधुनिक संसाधन सुविधाओं का न होना आदि।

(ख) और (ग) इस प्रकार हुए घाटों का वैज्ञानिक आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रतिदिन 10 मी. टन की क्षमता का एक एक्स्पेलर डिजाइन तथा निर्मित किया गया है। खली से प्राप्त होने वाले तेल का प्रतिशत पारम्पारिक एक्स्पेलर की तुलना में 2% अधिक है। तथापि, वाणिज्यिक पैमाने पर एक्स्पेलर की उपयुक्तता और आर्थिक रूप से इसकी व्यवहार्यता, प्रमाणित नहीं है इसके प्रदर्शन हेतु सहायता दी जा रही है।

असिंचित भूमि के संबंध में अनुसंधान और अन्वेषण

1347. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि अनुसंधान तथा अन्वेषण संस्थानों को तीन चौथाई कृषि भूमि के बारे में जो सिंचाई के लिए या तो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है अथवा उसमें बिना सिंचाई के ही कृषि उत्पादन किया जाता है, अनुसंधान तथा अन्वेषण कार्य प्रारम्भ करने संबंधी कोई निर्देश दिये हैं ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उस प्रगति के को साधारण किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान प्रयोजना के 23 सहकारी केन्द्रों और अन्य फसल सुधार प्रायोजनाओं के तहत किये गये अनुसंधान के फल-स्वरूप बड़े पैमाने पर अपनाये जाने के लिए सुधरी बारानी खेती की तकनीकें मुहैया कराई गयीं।

(ग) हां।

(घ) वारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत 99 जिलों की 9.28 लाख हैक्टर भूमि आएगी। सुधरी बारानी खेती पद्धतियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा चलाये जाने वाले विस्तार कार्य-कलाप का एक अंग हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी सहयोग से 47 स्थानों पर आदर्श जलसंभरों के रूप में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रायोजनायें तैयार की गई हैं।

Setting up of Market intervention Fund

1348. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Miniter of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set-up a Rupees 30 crores Market Intervening Fund; and

(b) if so, what are the main objectives thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : (a) and (b). In view of the speculative nature of the edible oil trade provision has been made for creation of a market intervention fund to be built by the National Dairy Development Board to meet possible losses in market intervention operations. This fund would be created from the surpluses of market intervention ope-

rations after realising the overhead costs of the National Dairy Development Board. The surpluses would be credited to this fund up to a limit of Rs. 30 crores beyond which any surpluses would accrue to the Government. The losses, if any, from the market intervention operations will be charged by the National Dairy Development Board to this market intervention fund.

Programmes of CAPART

1349. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a Council for Advancement of People Action and Rural Technology to assist the programmes in Rural areas; and

(b) if so, what are the details thereof and the number of such programmes introduced so far, State-wise ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : (a) Yes, Sir.

(b) The Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) has been set up on 1st September, 1986 with the merger of People's Action for Development (India) and Council for Advancement of Rural Technology. The objectives of CAPART are to encourage, promote and assist voluntary action in the implementation of projects for the enhancement of rural prosperity and to strengthen and promote voluntary efforts in rural development. CAPART provides assistance to Voluntary Organisations all over India by funding programmes of rural development. State-wise number of projects sanctioned by CAPART from its inception to 18-2-1990 is given in the enclosed Statement.

Statement

Sl. No.	States	No. of projets sanctioned
1.	Andaman & Nicobar	***
2.	Andhra Pradesh	235
3.	Arunachal Pradesh	1
4.	Assam	57
5.	Bihar	288
6.	Chandigarh	6
7.	Dadra and Nagar Haveli	***
8.	Delhi	69
9.	Goa, Daman & Diu	***
10.	Gujarat	123
11.	Haryana	39
12.	Himachal Pradesh	36
13.	Jammu & Kashmir	9
14.	Karnataka	132
15.	Kerala	109
16.	Lakshadweep	***
17.	Madhya Pradesh	115
18.	Maharashtra	55
19.	Manipur	94
20.	Meghalaya	5
21.	Mizoram	3
22.	Nagaland	1
23.	Orissa	145
24.	Pondicherry	5
25.	Punjab	4
26.	Rajasthan	142
27.	Sikkim	***
28.	Tamil Nadu	301
29.	Tripura	2
30.	Uttar Pradesh	509
31.	West Bengal	416
	TOTAL	3101